PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Duniya, New Delhi
Tuesday, 27th September 2011, Page: 9
Width: 12.28 cms Height: 11.94 cms, Ref: pmin.2011-09-27.68.84

सरकारी शोध संस्थानों पर दवा कंपनियों की नजर

धनंजय

■ मर्क ने 'इंडिया इनोवेशन अवार्ड' के जरिए की शुरुआत

नई दिल्ली। बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सहित बड़े बड़े सरकारी मेडिकल शोध संस्थानों पर डोरे डालने को बेताब हैं। दुनिया की चंद बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों में एक मर्क ने 'इंडिया इनोवेशन अवार्ड' के जरिए इसकी शुरुआत कर दी है। इसके तहत कंपनी हर साल भारत के सरकारी मेडिकल शोध संस्थानों में कार्यरत तीन उन चिकित्सा वैज्ञानिकों को क्रमश: 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एवं 10 लाख रुपए देगी जिन्होंने लाइफ साइंसेज शोध में कोई आविष्कार किया है। कंपनी उनके उत्पादों को बाजार में प्रवेश करने एवं उसे पूरी दुनिया में प्रचारित करने का काम भी करेगी।

हालांकि यह महज शुरुआत है। कंपनी की नजर है दवा के आविष्कार के लिए भारत के सरकारी मेडिकल शोध संस्थानों के साथ मिल कर काम करने की योजना पर। यही संदेश देने के लिए कंपनी ने सोची समझी रणनीति के तहत इस अवार्ड की घोषणा के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के स्थापना दिवस को चुना। इधर कंपनी पुरस्कार की घोषणा कर रही थी, उधर विज्ञान भवन में स्थापना दिवस पर समारोह हो रहा था। भारत मेडिकल आविष्कार का हब बनने जा रहा है, मर्क के कर्णधारों की बातों से इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। सीईओ डॉ. कार्ल-लुडविग ने 'नईदुनिया' से बातचीत में कहा कि आविष्कार के लिए भारत को अब पश्चिमी देशों से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। मर्क भारत की चिकित्सा वैज्ञानिक बिरादरी के साथ पार्टनरशिप करने को आतुर है। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद के अपने भाषण में अगले दशक को इनोवेशन (सृजन) दशक का नाम दिया है तो सही दिया है। इस अवार्ड को कंपनी की लाइफ साइंसेज शाखा मर्क मिल्लीपोर ने शुरू किया है। इस प्रभाग की इंडिया शाखा के प्रमुख प्रांतिक मुखर्जी ने 'नईदुनिया' से बातचीत में कहा यह तो शुरुआत है। हमने भारत में इनोवेशन की अकूत संभावना देखी है।

दवा कंपनियां भारत के सरकारी शोध संस्थानों के साथ पार्टनरशिप को आतुर हैं, लेकिन सरकारी हैलकों में उन्हें अब तक शक की निगाहों से देखा जाता रहा है। पीएम मनमोहन सिंह ने एम्स के क्रिया कलापों को ठीक करने के लिए वैलियाथन कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एम्स के इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन वहां की फैकल्टी ने ही इसका विरोध कर दिया।